(d) if so, at what level of consideration the project is lying and when Government will start the actual work; and

(e) if not, what are the reasons for not considering such vital project from defence point of view?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) The defence authorities have not proposed construction of water canal on the Kutch border of India as a defence measure.

(c) to (e) Do not arise in view of reply to part (a) & (b) of the question.

Sharing of post of D.G.Q.A.

*407. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA': Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether a commitment of sharing of posts in DGQA between Service Officers and civilian DQAS Officers in the ratio of 50:50 at each level was made by the Secretary, (DP&S);

(b) if so, the details of actual holding by the two cadres, level-wise;

(c) whether it is a fact that the civilian DQAS Cadre Officers have been deprived of 50% posts at the levels of Director, Additional Director, Joint Director and equivalent grades; and

(d) if so, the details thereof and the reasons therefor, and the steps taken to restore parity between the two streams?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

1. In December 1979, the then Secretary Defence Production & Supplies, had proposed that posts in Directorate General of Inspections (DGI) at the level of Senior Scientific Officer I (SSO I) and above should be shared equally by the Civilian and Service Officers and that no post should be reserved for either category.

2. Thereafter Government appointed a Committee of Officers on 5.12.1981 to recommend on the bifurcation of posts on the basis of functions and job content so that separate channels for promotion could be provided for Civilian and Service Cadre.

3. The Committee identified posts accordingly to be manned by the two Cadres. A ratio of 44:56 of Civilian to Service Officers emerged. Govt accepted the recommendation in August 1982. The existing strength of the Civilian Cadre to the Service Cadre is in the ratio of 42:58. The ratio of Civilian and Service officers actually in position at SSO I level and above is 40.8:59.2. Posts, postions and responsibilities are assigned to each of the cadres keeping in view the requirements, exigencies and career prospects.

पर्याटक स्थलों पर प्रदूषण

*408. **श्री बरिजिन्दर सिंह**: क्या पर्यटक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि**:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 1998 के "जनसत्ता" में "पर्यटन विकास की कीमत" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच हे कि देश के अनेकों पर्यटक स्थल कूडा कचरे के ढेरों से लदे पडे हैं जिससे समूचा क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) जी, हां,

(ख) और (ग) सरकार, अनियोजित पर्यटन विकास से पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर पडने वाले हर सम्भव गलत प्रभाव के प्रति जागरूक है। ऐसे गलत प्रभाव से बचने के लिए उपाय किये गए हैं, यथाः

1. पारिस्थितिकी और पर्यवरण के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन के सतत विकास को सरकार की पर्यटन नीति का आधार स्तम्भ बनाया गया है।

2. पर्यटन मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाए गए मानकों के कडाई से अनुपालन के

लिए राज्य सरकारों, यात्रा व्यवसायियों एवं अन्य के साथ लगातार विचार-विमर्श करता रहता है।

3. पर्यटन मंत्रालय ने पारिस्थिति की पर्यटन नीति और दिशानिर्देश बनाए हैं। पारिस्थितिकी और पर्यटन के सतत विकास के प्रति जागरुकता अभियान भी चलाए गए हैं।

4. हिमालय क्षेत्र और जल क्षेत्र आदि जैस पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में क्षरण को रोकने के लिए आवश्यक संसाघन उपलब्ध कराने हेतु विशेष अध्ययन कराए गए हैं।

टिहरी बांध का कार्य पूरा किया जाना

*409. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी**: क्या विद्युत मंत्री 3 जून, 1998 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं. 822 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संशोधित अनुमानों के अनुसार सन् 2002 तक उक्त योजना को पूर्ण करने के लक्ष्य की रूपरेखा क्या है;

(ख) प्रति वर्ष के लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) टिहरी नगर को कब तक खाली करवा लिया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) चालू किए जाने के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I (1000 मे. वा.) को मार्च, 2002 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। परियोजना को पूरा किए जाने हेतु वर्षवार लक्ष्य विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) कॉफर बांध का ई. एल. 661 मीटर के स्तर तक का निर्माण जून, 1996 में पूरा कर लिया गया है। मानसून के महीनों (जुलाई-सितम्बर) के दौरान पर्याप्त चेतावनी के फलस्वरुप पिछले 32 वर्षों में देखे गए जल निःसरण के आधार पर जिन क्षेत्रों के प्रभावित होने की आशंका है, उस क्षेत्र में रह रहे लगभग 300 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना आवश्यक है। इन परिवारों को बसाने के लिए जिला प्रशासन के साथ परामर्श करके टिहरी हाईड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा अस्थायी प्रबंध किए गए हैं। जलाशय को अवरुद्ध करने से पूर्व ही पुराने टिहरी टाउन से जनता को हटा लिया जाएगा।

विवरण

टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना चरण-1 (1000 मे.वा.) को पूरा किए जाने के वर्ष वार लक्ष्य

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य
1.	1998-99	I.प्रमुख बांध को ई. एल. 620.0 मीटर तक उठाना। II.विद्युत गृह को ई. एल. 605.0 मीटर तक की भूमिगत खुदाई पूरी करना III.चार नियंत्रण शाफ्टों की खुदाई पूरी करना। IV.टेल-रेस सुरंगों की खुदाई पूरी करना।
2.	1990-2000	I.प्रमुख बांध को ई. एल. 660.0 मीटर के स्तर तक उठाना। II.विद्युत गृह को ई. एल. 583.0 मीटर तक की भूमिगत खुदाई पूरी करना III.शॉफ्ट ट्यूब की भूमिगत खुदाई पूरी करना। IV.हैड-रेस सुरंगों में कंक्रीट लाइनिंग पूरी करना। V.250 मे. वा. प्रत्येक की चार उत्पादन यूनिटों का उत्थापन आरंभ करना।
3.	2000-2001	i.प्रमुख बांध को ई. एल. 720.0 मीटर के स्तर तक उठाना। ii.विद्युत गृह की आंशिक कंक्रीटिंग पूरी करना। iii.पेन-स्टॉकों की कंक्रीटिंग पूरी करना।